

यवहार में समानता समान कार्यकारी
आटीकल (14) भारतीय संविधान-

हो बनाई जाना चाहिए ओम प्रकाश
राम कोर्ट;

प्रकाश वाण्येय वि. यूनिन ऑफ
ए के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार

कालावाधि या विशेष प्रयोजन के
(II) म. प्र. बी. नोट 182 इनको
1987 म. प्र. ला. ज. 173।

सकता है और न सेवा समाप्त को
न ज. 376; ओ.पी. भण्डारी वि.
म. प्र. बी. नोट 113 सुप्रीम कोर्ट;
(1);

(जिस गोपाल वि. स्टेट, 1986 ज.

दो को भरने के लिये उपलब्ध है
मिस्टर सागर, 1986 (II) म. प्र.

जाना चाहिए और आरोप पत्र में
किया जा सकता के.एन. मिश्रा
प्रसन्न श्रीवास्तव वि. म. प्र. ला. ज.

नी में दी गई किन्तु उन्हें कर्मचारी
पा जा सकता (आर. एस. पाठाशर
86)।

नता के सिद्धान्तों के आधार पर
किये गये हैं कायम नहीं रखे जा

ना चाहिए (एस.सी. वैरा वि.

न व्यवहार आटीकल 16, 14
वि. स्टेट म. प्र. 1986 म. प्र.

जैन 1986 ज. ला. ज. 791।

(लगातार सेवा में रहना) मारा
वि. स्टेट म. प्र. 1986 (1)

ला. ए.एस. संघ वि. स्टेट

प्रश्न सं. [क. 278]

पटवारियों की नियुक्ति, योग्यताएं तथा दण्ड सम्बन्धी हिदायतें : 9

नियम 7. पटवारियों का स्थानान्तरण- किसी पटवारी का स्थानान्तरण उसी उप-सम्भाग के एक हल्के से दूसरे हल्के में उपखंडीय अधिकारी (उप-संभागीय अधिकारी) द्वारा तथा एक उप-संभाग से दूसरे उप-संभाग में कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा। स्थानान्तरण के प्रस्ताव, तहसीलदार द्वारा अधीक्षक, भू-अभिलेख के माफ़त भेजे जायेंगे।

टिप्पणी (1)-(7) नियम

(1) पटवारियों के एक हल्के (Circle) से दूसरे हल्के में तबादला S.D.O. कर सकेगा।
(2) कलेक्टर एक Sub-Division तहसील परगना से दूसरे तहसील परगने में जिले के भीतर पटवारी का तबादला कर सकेगा।

(3) तबादले के प्रस्ताव तहसीलदार परगने का अधिकारी S.L.R. के द्वारा S.D.O. को भेजेगा।

(4) सर्विस लाॅ- में तबादला एक सहज क्रम है किन्तु ऐसे आदेश को दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है- एक तो- यदि आदेश दुर्भावना पूर्ण दिया गया हो। दूसरे- कानूनी उपबन्धों- नियमों के प्रतिकूल दिया गया हो- सुरेश कुमार शर्मा वि. म्युनिसिपल कौंसिल अम्बाला- 1994 (1) म. प्र. बुडीशियल रिपोर्ट 198 डीवी हाईकोर्ट (जस्टिस एस.के. दुबे तथा जस्टिस के. एम. वाण्डे) यूनिन ऑफ इंडिया वि. एस.एन. अम्बाला 1993 ए.आर. सुको बीकली 1753)

(दुर्भावना- पक्षों के तथ्यों से समझी जा सकती है- दिनेश कुमार शर्मा वि. म. प्र. दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादा, 1994 (1) म. प्र. बुडी. रिपोर्ट 306- जस्टिस एस.के. दुबे, जस्टिस एस.के. चावला- डी.जी. हाईकोर्ट- ऐसा तबादला नहीं किया जाना चाहिए जिससे परिणाम में employer का परिवर्तन होते हो या जिसके फलस्वरूप यूनिनर्स के मुकाबले में नियोजित आवेदक के पद की हैसियत की तथा वेतन की अवगति होती हो।) दिनेश कुमार शर्मा वि. म. प्र. दुग्ध महासंघ (Vol. 13) (समैन्द्र राय वि. यूनिन ऑफ इंडिया ए.आर. 1993 सुकोर्ट 1236) पैरा 19, 20 में उद्धृत दिनेश कुमार वि. दुग्ध महासंघ म. प्र. 1994 (1) म. प्र. बुडी. रिपोर्ट 306)

नियम 8. कोई भी पटवारी उप-संभागीय अधिकारी द्वारा हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा।
टिप्पणी- (1)-(8) नियम

(1) म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अध्याय 9 में भू-अभिलेख सम्बन्धी प्रावधान न किये गये हैं जिनमें भाग 104 में पटवारों के हलकों की विवरणा तथा उनमें पटवारियों की नियुक्ति के बारे में निर्दिष्ट है।

भाग 104 (2) में- 'कलेक्टर भू-अभिलेख रखने तथा उनके शुद्धिकरण के लिये और अन्य कर्तव्यों के लिये जैसे कि राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक पटवारी हल्के में एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा।' ऐसा प्रावधान है। भू-अभिलेख संहिता की भाग 2 (1) (ड) के अनुसार संहिता के उपबन्धों के अधीन रखे गये भू-अभिलेख होते हैं।

भाग 106 (2) में नगर सर्वेक्षक तथा सहायक नगर सर्वेक्षक को उनके भारसाधन के अधीन आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में भाग 28, 109, 110, 112, 118 तथा 120 (भू-राजस्व संहिता, 1959) के प्रयोजनों के लिये पटवारी समझे जाने का प्रावधान किया गया है।

(राजस्व) उपखंडीय अधिकारी द्वारा पटवारी की पदच्युति अधिकार के भीतर है- (मोतीलाल वि. म. प्र. दुग्ध 1995 राजस्व निर्णय 67 (डी.जी. हाईकोर्ट)।

(2) उप-संभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) उप-खंडीय अधिकारी से आशय है। जब पटवारी को हटाया या पदच्युत किया जाता है तो इसे भाग 104 (2) भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन दिया